शोधामृत
(कला, मानविकी और सामाजिक विज्ञान की अंतर्राष्ट्रीय सहकर्मी समीक्षित, मूल्यांकित, त्रैमासिक शोध पत्रिका)

ISSN : 3048-9296 (Online)
3049-2890 (Print)
IIFS Impact Factor-5.375
Vol.-3; issue-3 (July-Sept.) 2026
Page No- 170-175
©2026 Shodhaamrit
DOI : 10.71037/Shodhaamrit.v3i3.23
https://shodhaamrit.gyanvividha.com

Author's :

1. डॉ. सुरेंद्र
सहायक आचार्य, पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय.

2. निशा
शोधार्थी, पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय.

Corresponding Author :

डॉ. सुरेंद्र
सहायक आचार्य, पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय.

शिक्षण में एआई: एक विश्लेषण

मुख्य शब्द: एआई, शिक्षण में एआई, उच्च शिक्षा, एआई तकनीक।

भूमिका: कोरोना महामारी के बाद देश के हर क्षेत्र में काफी बदलाव आया है। कंपनियों में जॉब करने से लेकर स्कूल-कॉलेज व विश्वविद्यालयों में पढ़ाई तक के तरीके एकदम बदल गए हैं। आज शिक्षण को बिना डिजिटल तकनीक के नहीं सोचा जा सकता है। वैसे तो कंप्यूटर और इंटरनेट ने पहले ही शिक्षा को काफी बदल दिया था। कोविड-19 के बाद शिक्षकों के पढ़ाने के तरीके बदल गए और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई ने चीजों को पूरी तरह से बदल दिया है। एआई भारत में न सिर्फ स्कूल लेवल बल्कि कॉलेज-यूनिवर्सिटी में उच्च शिक्षा में भी अलग-अलग तरीके से काम कर रहा है।

सितंबर 2025 में, दुनिया की मशहूर एआई कंपनी, ओपनएआई ने AICTE से जुड़े टेक्निकल इंस्टीट्यूशन में छात्रों और शिक्षकों को 150,000 निशुल्क 'चैटजीपीटी गो' लाइसेंस बांटे, जिसमें टियर-2 और टियर-3 शहरों पर खास ध्यान दिया गया (Careers360, 2025; Singh et al., 2026)। IIT मद्रास और IIT कानपुर में अलग-अलग लेवल पर बात हो रही है। वहां के प्रोफेसरों का कहना है, "हर कोर्स में एआई का फ्लेवर होना चाहिए," जिस कारण एआई लिटरेसी कंप्यूटर साइंस से लेकर सिविल इंजीनियरिंग और ह्यूमैनिटीज तक हो गई है(ThePrint, 2026)। वहीं, दूसरी तरफ, बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी ने 40 परसेंट से ज़्यादा एआई से लिखा कंटेंट मिलने के बाद दर्जनों पीएचडी थीसिस रिजेक्ट कर दीं, जिससे शोधार्थियों को उन्हें दोबारा लिखना पड़ा (Education for All in India, 2026)। एक तरफ, हर क्लासरूम में एआई लाने की राष्ट्रीय कोशिश है और दूसरी तरफ, छात्रों द्वारा हद से ज्यादा किया जा रहा इसका उपयोग, इंडियन हायर एजुकेशन में बहुत से सवाल उठा रहा है।

यह अंतर स्कूलों के मुकाबले यूनिवर्सिटी लेवल पर ज़्यादा मायने रखता है। स्कूलों में छात्र एआई का लापरवाही से इस्तेमाल करके सीखने में शॉर्टकट का रिस्क ले रहे हैं। वहीं, मास्टर्स या डॉक्टरेट कर रहे छात्र अपने प्रोजेक्ट, असाइनमेंट और तो और शोध का काम

एआई से करा रहे हैं और यह गंभीर विषय है। भारत की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में बड़े पैमाने पर शिक्षा में एआई को जोड़ने की बात कही गई है (मिनिस्ट्री ऑफ़ एजुकेशन, 2020), और इंडियन हायर-एजुकेशन इंस्टीट्यूशन्स के 2025 के FICCI-EY-पार्थेनन सर्वे में पाया गया कि आधे से ज़्यादा इंस्टीट्यूशन्स के पास पहले से ही एक फॉर्मल एआई पॉलिसी थी, जिसमें जेनरेटिव एआई का इस्तेमाल टीचिंग मटीरियल, ट्यूशन और यहाँ तक कि ग्रेडिंग के लिए भी किया जा रहा था (EY इंडिया, 2025)। इस समीक्षा में यह महत्वपूर्ण तर्क दिया गया है कि भारत में "स्किलिंग-फर्स्ट, गवर्नेंस-लेटर" पर जोर रहा है, जिसका अर्थ है एआई-पहुँच को तो बढ़ावा मिला है, किंतु राष्ट्रीय स्तर पर कक्षाओं में इसके इस्तेमाल को लेकर दिशानिर्देशों को लगभग पूरी तरह से अनदेखा किया गया है (Singh et al., 2026)। इस शोधपत्र का उद्देश्य यह समझना है कि कॉलेज-यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले प्रोफेसर आज की जरूरत के हिसाब से एआई का इस्तेमाल करते हुए कैसे एक संतुलन स्थापित कर रहे हैं।

साहित्यिक समीक्षा: भारतीय उच्च शिक्षा में AI पर शोध इतनी तेज़ी से बढ़ा है कि साल 2026 में एक स्कोपिंग रिव्यू किया गया, जिसमें एक हज़ार से अधिक रिकॉर्ड्स को छानकर 236 योग्य स्रोत निकाले गए, और अब इस रिव्यू को इस क्षेत्र में एक अहम शोध के तौर पर लिया जा रहा है (Singh et al., 2026)। यह समीक्षा AI अपनाए जाने के चार क्षेत्र बताती है: शिक्षण-अधिगम, मूल्यांकन, शोध-सहायता, और संस्थागत प्रशासन; और पाती है कि लगभग पांचवें हिस्से के अध्ययनों में अकादमिक सत्यनिष्ठा या शैक्षणिक ईमानदारी से जुड़ी चिंताएं मौजूद हैं, जो किसी एक विषय-क्षेत्र तक सीमित नहीं बल्कि हर अनुशासन में फैली हुई हैं। इस शोधपत्र के लिए इसका सबसे अहम निष्कर्ष संरचनात्मक है: भारत की नियामक प्रतिक्रिया "पहले कौशल, बाद में शासन-व्यवस्था" वाली रही है यानी AICTE-OpenAI साझेदारी जैसी पहलों से पहुंच तो बढ़ाई गई, पर कक्षा-स्तर पर एआई का इस्तेमाल, इसके इस्तेमाल को उजागर करना और मूल्यांकन-प्रणाली को राष्ट्रीय स्तर पर लगभग अनछुआ छोड़ दिया गया (Singh et al., 2026)।

फैकल्टी के स्तर पर, Asian Education and Development Studies में छपे 2026 के एक अध्ययन ने यह जांचा कि आखिर कौन-सा कारक तय करता है कि कोई भारतीय प्रोफेसर पढ़ाई में जेनरेटिव AI अपनाएगा या नहीं, और पाया कि संस्थागत आदेश या छात्रों की मांग नहीं, बल्कि फैकल्टी की तैयारी और डिजिटल दक्षता ही निर्णायक कारक हैं (Razi-ur-Rahim et al., 2026)। इससे एक और निष्कर्ष समझ में आता है जो स्कोपिंग रिव्यू में भी सामने आया है: भारतीय फैकल्टी का AI-TPACK (यानी AI से जुड़ा तकनीकी-शैक्षणिक-विषयगत ज्ञान) स्तर "निम्न से मध्यम" ही है, और यह अनुशासन तथा संस्थान के अनुसार काफी अलग-अलग है (Singh et al., 2026)। भारतीय उच्च शिक्षा शिक्षकों द्वारा ChatGPT को अपने शिक्षण में शामिल करने पर हुए एक परिघटना-विज्ञान (phenomenological) अध्ययन ने इस स्थिति को "संस्थागत अनिश्चितता" कहा, यानी प्रोफेसर बिना किसी नीति के सहारे के, अकेले ही AI को लेकर नैतिक फैसले ले रहे हैं, और यह किसी एक शिक्षक की व्यक्तिगत चूक नहीं बल्कि एक व्यवस्थागत खाली जगह है (Sharma & Rai, 2026, Singh et al., 2026)।

मूल्यांकन से जुड़ा साहित्य उच्च शिक्षा के लिए एक और तीखी चिंता सामने रखता है: स्कोपिंग रिव्यू में उद्धृत कई अध्ययन बताते हैं कि ChatGPT जैसे टूल्स भारत की प्रमुख व्यावसायिक और प्रवेश परीक्षाओं, जैसे GATE, NEET, और विश्वविद्यालय-स्तर की क्वालिफाइंग परीक्षाओं में पास होने लायक अंक हासिल कर चुके हैं (Singh et al., 2026)। यह महज़ नकल की समस्या नहीं है; यह इस बात का सबूत है कि मूल्यांकन के कुछ पारंपरिक तरीके अब शायद यह फर्क करने में सक्षम ही नहीं रह गए कि छात्र की समझ है या एक चैटबॉट का जवाब।

शोध-सत्यनिष्ठा के मोर्चे पर, O.P. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के 2025 के एक अध्ययन में पाया गया कि अधिकतर भारतीय विश्वविद्यालयों ने अभी तक कोई AI-डिटेक्शन सॉफ्टवेयर लिया ही नहीं है, जिससे वे उस AI

से लिखे गए अकादमिक लेखन को पहचानने में असमर्थ हैं जो सामान्य नकल-जांच से आसानी से बच निकलता है (Gupta et al., 2025) और इस खाली जगह को भरने के लिए यूजीसी ने फिलहाल बस अपने 2018 के नकल-रोधी नियमों को, जो जेनरेटिव AI के मौजूदा स्वरूप में आने से पहले बनाए गए थे, उस समस्या पर खींच-तान कर लागू करना शुरु किया है, जिसके लिए वे नियम सिरे से बने ही नहीं थे (UGC, 2018, Singh et al., 2026)।

शोध प्रश्न : RQ1: भारतीय प्रोफेसर और उच्च शिक्षा संस्थान स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टरल शिक्षण में AI को किस तरह शामिल कर रहे हैं?

RQ2: भारत में उच्च-शिक्षा स्तर पर शिक्षण, शोध-निर्देशन और छात्रों के सीखने की प्रक्रिया में AI के इस्तेमाल से क्या लाभ मिल रहे हैं?

RQ3: AI के इस्तेमाल से, खासकर अकादमिक सत्यनिष्ठा, मूल्यांकन की विश्वसनीयता, और शोध की मौलिकता के मामले में, भारतीय उच्च शिक्षा को क्या नुकसान हुए हैं?

RQ4: व्यक्तिगत स्तर पर भारतीय संस्थान शिक्षण-पद्धति और मूल्यांकन को किस तरह पुनर्गठित कर रहे हैं ताकि एक व्यावहारिक संतुलन बनाया जा सके, और इन विविध प्रतिक्रियाओं से एक प्रोफेसर अपने खुद के तरीके को तय करने के लिए क्या सीख सकता है?

शोध-पद्धति: यह एक गुणात्मक, व्याख्यात्मक शोध-पत्र है जो फैकल्टी के बीच किए गए प्रत्यक्ष क्षेत्र-अध्ययन के बजाय द्वितीयक स्रोतों के विश्लेषण पर आधारित है। यह क्षेत्र कितनी हाल की गति से विकसित हुआ है, इसका अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि ऊपर चर्चा किए गए स्कोपिंग रिव्यू के अनुसार भारतीय उच्च शिक्षा में AI से जुड़े 83 प्रतिशत साहित्य नवंबर 2022 के बाद के हैं (Singh et al., 2026)। इसे देखते हुए एक दस्तावेज़-विश्लेषण पद्धति अपनाई गई, जिसमें एक राष्ट्रीय फैकल्टी-अपनाव सर्वेक्षण (EY India, 2025), पीयर-रिव्यूड और प्रीप्रिंट अनुभवजन्य अध्ययन (Razi-ur-Rahim et al., 2026; Singh et al., 2026; Gupta et al., 2025), आधिकारिक नियामक दस्तावेज़ (शिक्षा मंत्रालय, 2020; यूजीसी, 2018), और अलग-अलग विश्वविद्यालयों पर हाल की संस्थागत रिपोर्टिंग (ThePrint, 2026; Civilsdaily, 2026; Careers360, 2024, 2025) को एक साथ जोड़कर देखा गया। स्रोतों को चुनते समय समसामयिकता (लगभग सभी 2024–2026 के बीच के), खुली पहुंच, और एक ही संस्थागत दृष्टिकोण की बजाय कई नज़रियों, राष्ट्रीय नीति, व्यक्तिगत फैकल्टी, संस्थागत प्रशासन, और छात्र-केंद्रित रिपोर्टिंग को शामिल करने का ध्यान रखा गया।

डेटा विश्लेषण :

फायदे: एआई का सबसे स्पष्ट फायदा शिक्षण-सामग्री तैयार करने में मिलता है। FICCI-EY-Parthenon सर्वेक्षण में पाया गया कि सर्वेक्षण में शामिल 53 प्रतिशत उच्च शिक्षा संस्थानों में जेनरेटिव AI का इस्तेमाल पहले से ही शिक्षण-सामग्री बनाने में हो रहा है, वहीं AI ट्यूशन और चैटबॉट्स 40 प्रतिशत संस्थानों में, अनुकूलनशील लर्निंग प्लेटफॉर्म 39 प्रतिशत संस्थानों में, और स्वचालित मूल्यांकन 38 प्रतिशत संस्थानों में उपयोग हो रहा है (EY India, 2025)। यह वही पैटर्न है जो स्कूल-स्तर के शिक्षक बहुत कम संस्थागत ढांचे के बावजूद अपनाते हुए दिख चुके हैं, बस यहां यह विश्वविद्यालय के पैमाने पर हो रहा है।

दूसरा फायदा शोध-निर्देशन और अकादमिक उत्पादकता में मिलता है। उदाहरण के लिए, IISER पुणे की फैकल्टी अब डॉक्टरल शोधार्थियों को यह प्रशिक्षण देती है कि वे साहित्यिक समीक्षा के लिए, AI मॉडल का उपयोग करके सैकड़ों शोध-पत्रों में दोहराए जाने वाले विषयों और विरोधाभासों को सामने ला सकें। यह काम जो पहले हफ्तों में होता था, अब घंटों में सिमट गया है, और दवा-खोज जैसे क्षेत्रों में AI द्वारा सुझाए गए संभावित रास्तों की समीक्षा आगे बढ़ने से पहले इंसान-शोधकर्ता ही करते हैं (ThePrint, 2026)। यह स्कूल-स्तर पर AI अपनाए जाने से बिल्कुल अलग एक उपयोग है: यह कक्षा में पढ़ाई-लिखाई भर को नहीं, बल्कि विश्वविद्यालय के शोध-कार्य को ही लक्षित करता है।

तीसरा, कई संस्थान AI साक्षरता को कंप्यूटर साइंस तक सीमित एक विशेषज्ञता की बजाय, हर अनुशासन के लिए ज़रूरी परिणाम मान रहे हैं। BITS पिलानी अब अनुशासन चाहे जो भी हो, पहले वर्ष के सभी छात्रों को AI कोर्स उपलब्ध कराता है, और IIT दिल्ली के निदेशक का कहना है कि लक्ष्य हर छात्र को AI-विशेषज्ञ बनाना नहीं बल्कि हर स्नातक को AI-साक्षर बनाना है, "सिविल इंजीनियर भी इसका इस्तेमाल इन्फ्रास्ट्रक्चर की योजना बनाने में कर सकते हैं, मानविकी के छात्र बड़े स्तर पर कंटेंट का विश्लेषण करने में" (ThePrint, 2026)।

चौथा, AICTE-OpenAI Learning Accelerator का टियर-2 और टियर-3 शहरों पर ज़ोर देना इस बात की एक वास्तविक कोशिश है कि यह फायदा भारत के महानगरीय, संसाधन-संपन्न संस्थानों से आगे भी पहुंचें (Careers360, 2025), हालांकि, बिना उचित मार्गदर्शन के सिर्फ इसकी पहुंच बढ़ा देना हानिकारक हो सकता है।

नुकसान और जोखिम: उच्च शिक्षा से जुड़ा सबसे बड़ा नुकसान डिग्री की साख को ही होने वाला क्षरण है। बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय का मामला है जहां 40 प्रतिशत से अधिक AI से लिखा गया कंटेंट पाए जाने पर दर्जनों पीएचडी थीसिस अस्वीकार कर दी गईं। यह कोई अकेली घटना नहीं, बल्कि इस बात की एक झलक है कि डॉक्टरल स्तर पर बिना किसी नियंत्रण के यह बदलाव कैसा दिख सकता है, जहां पूरी कवायद का मक़सद ही ज्ञान में एक प्रदर्शित, व्यक्तिगत और मौलिक योगदान होता है (Education for All in India, 2026)।

दूसरा, डिटेक्शन क्षमता इस समस्या के अनुपात में नहीं बढ़ पाई है। Gupta et al. (2025) ने पाया कि अधिकतर भारतीय विश्वविद्यालयों ने कोई AI-डिटेक्शन सिस्टम लिया ही नहीं है, और जहां सामान्य नकल-जांच सॉफ्टवेयर मौजूद भी है, वह आमतौर पर एआई से लिखे गए ऐसे कंटेंट को पकड़ने के लिए नहीं बना जो पढ़ने में मौलिक लगती है। यूजीसी का अपना नियामक ढांचा इस समस्या को और बढ़ा देता है, यूजीसी के 2018 के नकल-रोधी नियम, जो किसी विकल्प के अभाव में अब AI से बन रहे कंटेंट पर भी लागू किए जा रहे हैं, न तो AI कंटेंट को उजागर करने की कोई शर्त रखते हैं, न ही यह कोई पद्धतिगत मार्गदर्शन देते हैं कि संस्थान AI की मदद से किए गए काम की पहचान आखिर करें कैसे (Singh et al., 2026)।

1. तीसरा और अधिक बुनियादी मसला मूल्यांकन-प्रणाली की विश्वसनीयता का ही है। अगर जेनरेटिव AI टूल्स पहले से ही GATE, NEET और विश्वविद्यालय की क्वालिफाइंग परीक्षाएं पास कर सकते हैं (Singh et al., 2026), तो चिंता सिर्फ इतनी नहीं कि छात्र इनका इस्तेमाल करके नकल कर सकते हैं, बल्कि यह भी कि इन परीक्षाओं का एक बड़ा हिस्सा शायद अब यह फर्क करने में सक्षम ही नहीं रहा कि छात्र को वाकई विषय की समझ है या यह महज़ AI का सहज उत्पाद है, और इसे सिर्फ सख्त निगरानी से हल नहीं किया जा सकता।

चौथा, Sharma और Rai (2026) द्वारा दर्ज की गई "संस्थागत अनिश्चितता" है: व्यक्तिगत प्रोफेसर अपनी कक्षा में AI को लेकर बड़े नैतिक फैसले बिना किसी संस्थागत नीति के सहारे के ले रहे हैं, और स्कोपिंग रिव्यू इसे किसी एक शिक्षक की चूक नहीं बल्कि एक व्यवस्थागत समस्या मानता है (Singh et al., 2026)। इसे राष्ट्रीय स्तर पर फैकल्टी के निम्न-से-मध्यम AI-TPACK स्तर से और बल मिलता है, यानी बहुत से प्रोफेसर बिना किसी संरचित प्रशिक्षण के ही ये फैसले ले रहे हैं (Singh et al., 2026)।

सुझाव और निष्कर्ष: ऊपर दिए गए तर्कों के आधार पर, प्रोफेसरों और शोध-निर्देशकों के लिए कुछ ठोस व्यावहारिक सुझाव हो सकते हैं। जैसे कि AI का इस्तेमाल तैयारी और संश्लेषण के लिए करें। AI द्वारा तैयार लेक्चर कंटेंट या साहित्य-सारांश को बिना पढ़े इस्तेमाल करने की बजाय, उसकी समीक्षा और संपादन करें; यही "ह्यूमन-इन-द-लूप" सिद्धांत है जो अपेक्षाकृत सफल संस्थागत मॉडलों को अनिश्चितता वाले मॉडलों से अलग करता है। साथ ही, AI मानक परीक्षाएं पास कर सकता है, इसे सिर्फ निगरानी बढ़ाने की समस्या न मानकर एक

डिज़ाइन-संकेत मानें। संस्थान कुछ अलग मूल्यांकन डिज़ाइन करें, जैसे मौखिक परीक्षा, प्रोजेक्ट-आधारित काम, किसी नए कंटेंट का कक्षा में विश्लेषण करना ताकि छात्रों की तर्क-क्षमता की परीक्षा ली जा सके। इन कामों में AI तुरंत मदद नहीं कर सकता।

एआई के इस्तेमाल को उजागर करने का नियम स्पष्ट रूप से बताएं, उसे अनकहा न छोड़ें। Sharma और Rai (2026) का "संस्थागत अनिश्चितता" वाला निष्कर्ष यही दिखाता है कि नुकसान किसी खास नीति से नहीं बल्कि नीति के अभाव से होता है। जैसे अशोका विश्वविद्यालय में AI-नैतिकता को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाकर पढ़ाया जा रहा है, बजाय इसके कि छात्र खुद नियम समझ लें। एआई के नैतिक इस्तेमाल को उजागर करना, चुप्पी से कहीं बेहतर मॉडल है। खासकर डॉक्टरल शोध-निर्देशन के लिए। शोध-निर्देशकों को चाहिए कि वे हर ड्राफ्ट अध्याय में स्पष्ट रूप से यह अनिवार्य करें कि एआई के इस्तेमाल को उजागर किया जाएगा। ShodhShuddhi पोर्टल जैसे डिटेक्शन टूल्स को केवल सबमिशन के समय नहीं बल्कि शुरुआत में ही एक रचनात्मक जांच के तौर पर इस्तेमाल करें। साथ ही, गलत तरीके से एआई के इस्तेमाल की जिम्मेदारी शोध निर्देशक पर भी उतनी ही हो जितनी कि शोधार्थी पर (Research Experts, 2026)।

सबसे जरूरी है कि फैकल्टी अपने-आप एआई को अपना लेंगे और इसे सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, यह मान लेना सही नहीं है। उनके लिए एआई का प्रशिक्षण कराया जाना चाहिए ताकि उच्च शिक्षा में एडवांस्ड तकनीक को नैतिक तरीके से इसकी पूरी क्षमता के साथ छात्रों व संस्थान के विकास के लिए इस्तेमाल किया जा सके।

संदर्भ :

1. Agarwal, S., Arora, C., Athreye, S., Goyal, A., Gupta, P., Jain, A., Nayar, D., Rathore, S., Sinate, A., & Sinha, S. (2024). On the use of generative AI at IIT Delhi. IIT Delhi.
2. Careers360 (PTI). (2024, September 24). IIM Sambalpur to introduce AI-enabled teaching.https://news.careers360.com/iim-sambalpur-introduce-ai-enabledteaching
3. Careers360. (2025, September 5). AICTE partners with OpenAI to provide 1.5 lakh free ChatGPT Go licenses to educational institutions. https://news.careers360.com/aicte-partners-openai-provide-1-5-lakh-free-chatgpt-go-licenses-educational-institutions-iit-madras-ministry-of-education-ai
4. Civilsdaily. (2026). ClassGPT: How AI is reshaping campuses. https://www.civilsdaily.com/news/classgpt-how-ai-is-reshaping-campuses/
5. Education for All in India. (2026, February 10). Upholding academic integrity in educational research: UGC's crackdown on AI misuse in PhD theses and guidelines for researchers. https://educationforallinindia.com/upholding-academic-integrity-in-educational-research-ugcs-crackdown-on-ai-misuse-in-phd-theses-and-guidelines-for-researchers/
6. EY India. (2025, November 14). AI in higher education: 2025 survey & latest insights. https://www.ey.com/en_in/insights/education/harnessing-ai-in-higher-education-opportunities-and-the-road-ahead
7. Gupta, A., Mahaseth, H., & Bajpai, A. (2025). AI detection in academia: How Indian universities can safeguard academic integrity. Engineering Proceedings, 107(1), 26. https://doi.org/10.3390/engproc2025107026

8. Miao, F., & Holmes, W. (2023). Guidance for generative AI in education and research. UNESCO. https://www.unesco.org/en/articles/guidance-generative-ai-education-and-research
9. Ministry of Education, Government of India. (2020). National Education Policy 2020. https://www.education.gov.in/
10. Razi-ur-Rahim, M., Uddin, F., Chauhan, J., & Faisal, K. (2026). GenAI in Indian higher education: Faculty at the crossroads of adoption. Asian Education and Development Studies, 15(1), 41–72. https://doi.org/10.1108/AEDS-04-2025-0194
11. Research Experts. (2026, July). UGC AI plagiarism guidelines 2026: What Indian PhD students must know. https://www.researchexperts.in/ugc-guidelines-for-ai-plagiarism-2026/
12. Singh, S., Singh, B., & Pandey, C. S. (2026). Mapping artificial intelligence adoption, perceptions, and governance in Indian higher education: A scoping review [Preprint]. Research Square. https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-10639862/v1
13. ThePrint. (2026). AI is India's new learning craze. IIT courses, prompt workshops, research training. https://theprint.in/ground-reports/ai-is-indias-new-learning-craze-iit-courses-prompt-workshops-research-training/3025938/
14. University Grants Commission. (2018). UGC (Promotion of Academic Integrity and Prevention of Plagiarism in Higher Educational Institutions) Regulations, 2018. Government of India. https://www.ugc.gov.in

•